opted for allotments on hire purchase basis. However, as per the terms and conditions of the brochure 50 per cent of the registrants will be allotted flats on hire purchase basis.

(b) Registrants of the Scheme are likely to be allotted flats between two to three years from now.

भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता

396. **श्री राधाकिशन मालवीय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के पास खाद्यान्नों के भंडारण के लिए पर्याप्त संख्या में भंडार-गृह नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्नों के भंडारण संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढकी हुई भण्डारण क्षमता व्यस्ततम अवधि में खाद्यान्नों के स्टाक को रखने के लिए पर्याप्त नहीं है।

(ख) निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(i) भारतीय खाद्य निगम, सैन्ट्रल वैयरहाउसिंग कारपोरेशन और 16 राज्य भण्डागार निगमों द्वार अतिरिक्त ढकी हुई भण्डारण क्षमता का निर्माण करना। आशा है कि 1986–87 के दौरान 10.25 लाख मीटरी टन की क्षमता का निर्माण कर लिया जाएगा और 1987–88 के दौरान 9.00 लाख मीटरी टन की और क्षमता का निर्माण करने का अनुमान है ; और

(ii) विभिन्न स्रोतों से अतिरिक्त भण्डारण क्षमता किराये पर लेना।

"प्रयोगशाला से उपयोगशाला" (लेब टू लैंड) योजनाएं

397. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में अलग-अलग कितनी *"प्रयोगशाला से उपयोगशाला"* (लेब टू लैंड) प्रयोजनाएं चल रही हैं तथा प्रत्येक योजना पर कितना वार्षिक व्यय हो रहा है और इन योजनाओं के अन्तर्गत किस प्रकार का कार्य किया जाता है ;

(ख) बिहार में ऐसी योजनाएं किन-किन स्थानों पर चल रही हैं और ये किस हद तक सफल हुई हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में ये योजनाएं पिछड़ गई हैं;

(घ) "प्रयोगशाला से उपयोगशाला" का क्या अर्थ है और इस संबंध में कितने फार्मों में अनुसंधान कार्य का प्रदर्शन किया जा रहा है अथवा क्या इसका क्रियान्वयन भूमिहीन लोगों के बीच गायें, बकरियां आदि बांटकर किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत "प्रयोगशाला" और "उपयोगशाला" की कोई उपयोगिता नहीं है; और

(ङ) क्या सरकार इस योजना का नाम बदलकर "गरीब-छोटे-भूमिहीन किसानों को सहायता पहुंचाने वाली योजना" रखने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० प्रभु): (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में 101 प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम से संबंधित केन्द्र (मौजूदा संस्थान) हैं जिन्हें संलग्न विवरण (नीचे देखिये) में दिखाया गया है । इन केन्द्रों को अनुदान के रूप में 1.10.1986 से 31.3.87 तक 38.16 लाख रु० की राशि दी गई। प्रति वर्ष महत्वपूर्ण निवेशों के लिए प्रत्येक केन्द्र को प्रति परिवार 500 रु० के हिसाब से धन-राशि दी जाती है जिसका उपयोग